भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 584

जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है

नई कोयला खानें

584. श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

श्रीमती चिंता अनुराधाः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 99 नई कोयला खानों के विकास की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार वर्ष 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को 45 प्रतिशत से कम करने के अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) का पालन करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : केवल 99 कोयला खानें ही नहीं, बल्कि वर्ष 2020 में शुरू की गई वाणिज्यिक खनन के लिए सबसे पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक बोलीदाताओं को आवंटन के लिए कई और कोयला खानों की पेशकश की गई है। अब तक, वाणिज्यिक नीलामी के 7 दौर पूरे हो चुके हैं और 221 एमटीपीए की पीआरसी के साथ 91 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। वाणिज्यिक नीलामी का 8वां दौर दिनांक 15 नवंबर, 2023 को 35 खानों के लिए शुरू किया गया है। कुल मिलाकर, घरेलू कोयले की मांग को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में खानों का विकास किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान

कैप्टिव/वाणिज्यिक ब्लॉकों से कोयला उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	कैप्टिव (मि.ट.)	वाणिज्य (मि.ट.)	कुल (मि.ट.)
2020-21	63.14	शून्य	63.14
2021-22	84.17	1.15	85.32
2022-23	109.33	7.22	116.55
2023-2024 (नवंबर, 23 तक)	77.36	6.64	84

(ग) : भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50 प्रतिशत संचयी विद्युत स्थापित क्षमता हासिल करना है। वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन सीओ2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना; जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी के रूप में 'लाईफ' (एलआईएफई) (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के जन आंदोलन के माध्यम से संधारणीय जीवन शैली का प्रचार करना; जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलन; जलवायु अनुकूल और स्वच्छ विकास पथ अपनाना; घरेलू, नई और अतिरिक्त निधियाँ जुटाना और क्षमता निर्माण करना अन्य लक्ष्य हैं।

भारत ने धीरे-धीरे आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से अलग करना जारी रखा है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता 2005 और 2016 के बीच 24 प्रतिशत कम हो गई है। भले ही, भारत इस समस्या का हिस्सा नहीं है, यह समाधान का हिस्सा है, और जलवायु परिवर्तन का समाधान करने में अपने उचित हिस्से से कहीं अधिक काम किया है।

****